

an>

Title: Inclusion of Bhojpuri in the 8th Schedule of Constitution

***m02 माननीय सभापति:** श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' जी ।

संसद में माननीय सदस्य का यह पहला संबोधन है ।

श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' (आज़मगढ़) : माननीय सभापति जी, मैं आज पहली बार सदन में बोल रहा हूँ । अगर मुझ से कोई गलती हो जाए, तो आप सब लोग मुझे क्षमा कीजिएगा ।

सभापति जी, कहा जाता है कि भाषा हमारे अस्तित्व का मूल है । हम अपनी भाषा में बेहतर तरीके से सोच, समझ और अभिव्यक्त कर पाते हैं । महात्मा गांधी जी ने भी मातृभाषा के प्रति कृतज्ञ होने की बात कही है । इसी भावना के साथ पिछले पांच दशक से करोड़ों भोजपुरी भाषी एक आस लगाए बैठे हैं कि भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मिले, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए । लेकिन भोजपुरी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है । कभी तो भाषा के भेद का पाठ पढ़ा कर तो कभी नियमों की अस्पष्टता का हवाला दे कर, भोजपुरी भाषियों की मांग पूरी नहीं होने दी गई ।

सभापति जी, भारत से अलग मॉरिशस की पहल पर यूनेस्को ने भोजपुरी संस्कृति के गीत गवनी को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है । लेकिन पहले की केंद्र की सरकारों ने कभी कोई ठोस प्रयास नहीं किया । मोदी जी की सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भोजपुरी फिल्म समारोह का आयोजन किया, जिसके लिए मोदी सरकार का करोड़ों भोजपुरी भाषी हृदय से धन्यवाद करते हैं ।

सभी जानते हैं कि भोजपुरी भाषा की यह लड़ाई सन् 1967 से जारी है । सन् 1960 में पहली बार इसके लिए बिल लाया गया । तब से अब तक संसद में इसे ले कर 18 प्राइवेट मेंबर बिल्स भी आ चुके हैं । कई आंदोल भी हुए हैं । 16

देशों में बोली जाने वाली भाषा, जिसकी जड़ें लगभग हजार साल पुरानी हैं, जिसको भारत से बाहर कई देश स्वीकार कर चुके हैं । जिसको यूनेस्को सम्मान दे रहा है, क्या इस भाषा को अपने देश में संवैधानिक दर्जा का हक नहीं है?

वर्ष 2012 में हमें उम्मीद जगी थी, जब एक प्रस्ताव पर भाषण देते हुए गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी ने भोजपुरी में कहा था 'हम रऊआ सबके भावना के समझतानी' और मानसून सेशन में भोजपुरी को मान्यता देने के लिए हम बिल लाएंगे । लेकिन तत्कालीन सरकार ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया । तत्कालीन गृह मंत्री सदन में आश्वासन दे कर अपनी बात से पीछे हट गए और भोजपुरी के सम्मान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया ।

अब मोदी जी की सरकार है जो असंभव को भी संभव करने के लिए जानी जाती है । मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक जो संभव नहीं हो पाया, वह मोदी जी की सरकार में जरूर संभव होगा । हमारी भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार में अवश्य मिलेगा ।

सभापति जी, हमें पूरा भरोसा है कि सदन मेरी बातों पर गंभीरता से विचार करेगा । आपने मुझे इतना समय दिया और सम्मानित सदस्य साथियों ने सुना, इसके लिए मैं सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ।

जय भारत, जय भोजपुरी ।

माननीय सभापति : जिन्हें सम्बद्ध करना है, वे स्लिप भिजवा दें ।

... (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: सर ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : दादा, आप तो बोल चुके हैं । आप सम्बद्ध कीजिए । आप दो बार नहीं बोल सकते ।

... (व्यवधान)